

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 10 अप्रैल, 2008

विषय:—मै0 इण्टर आर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्रा0लि0 को जनपद उधमसिंहनगर की तहसील किच्छा के ग्राम किशनपुर में औद्योगिक प्रयोजन हेतु कुल 7.1533 है0 भूमि कय करने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या— 592/सात-स0भू0अ0/2008 दिनांक 9 जनवरी, 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 इण्टर आर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्रा0लि0 को उद्योग की स्थापना हेतु तहसील किच्छा के ग्राम किशनपुर के खाता संख्या— 235 में खसरा नं0-276क रकवा 7.1533 है0 भूमि जो पूर्व में मै0 रामाविजन लि0, पंजीकृत कार्यालय 203-205, रतन ज्योति 18, राजेन्द्र पैलेस, नई दिल्ली के नाम दर्ज माल अभिलेख है, को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:—

1— क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2— क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3— क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था

.....(2)

उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में स्पॉट जोनिंग क्षेत्र के लिये निश्चित सिद्धान्त/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

6- प्रस्तावित उद्योग का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा)-2005 के अनुरूप निर्माण होगा।

7- शासन द्वारा दी गयी भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी एवं भूमि का कब्जा प्राप्त होने के 180 दिन के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा।

8- प्रस्तावित औद्योगिक इकाई का निर्माण कार्य सीडा से लेआउट स्वीकृत कराने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9- स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

10- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

11- योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/ स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।

12- शासन द्वारा निर्धारित नीति/ मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/ मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक

प्रयोजन हेतु, भवन निर्माण का प्लान सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही, स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

13- स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को नियमित रूप से न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार दिया जायेगा।

14- इकाई द्वारा कय की जाने वाली भूमि का उपयोग Manufacturing Metal Sheeting Structures, Angles, Shapes & Sections for Industrial & Commercial Pre-Engineered Building उद्योग की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

15- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
 - 2- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
 - 3- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 4- सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 5- सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 6- निदेशक, उद्योग, इन्ड्रिस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
 - 7- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा, 2-न्यूकैन्ट रोड, सिडकुल, देहरादून।
 - 8- श्री अरविन्द नन्दा, डायरेक्टर मै0 इण्टर आर्च, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, ए-1/6, बसन्त विहार, नई दिल्ली।
 - 9- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
 - 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।